

ख़बर संक्षेप

ब्राण्डेड कंपनी के मिलते जुलते सामानों की आई बहार, आमजन की जिन्दगी को बन रहा खतरा?

हरिभूमि न्यूज़/साईंखेड़ा। मार्केट में इन दिनों डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की मांग खासी बढ़ गई है। क्योंकि खुले रस्मान में झुट्टाटा की गारंटी नहीं होने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के चलते लोग पैक आईटम की ओर आकर्षित होने से नहीं चुक पा रहे हैं, इसके चलते बाजार में नामी गिरामी कंपानियों की विभिन्न वैरिअटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद बन गए हैं। मगर गौर किया जावे तो बाजार में कंपनियों से मिलते जुलते बाँडों की भी बाद आई हुई है, यह सेहत पर क्या असर डालेंगे। इस बारे में न तो दुकानदार जान रहा है और न ही खाद्य विभाग को इतनी फुर्सत है कि इनकी जांच करें? बस दुकानदार तो कमीशन अधिक होने के फेरे में इन्हे बेचने में रुचि दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके चलते आम लोगों की जिन्दगी पूर्ण रूप से खरबे में दिखाई देने लगी है? अक्सर देखा जाता है कि बिना आई एस आई मार्क के भी प्रोडक्ट मार्केट में खुले आम बेचे जा रहे हैं जो इन्हें कारक बताये जाते हैं? मगर ग्राहकों की जानासुकता के अभाव के चलते एवं दुकानदार लालच के चक्कर में असली की सूरत में नकली कंपानियों के समान बेचते हुए आसानी से दिखाई देते हुए जान पड़ रहे हैं..? एक्सपायरी डेट का उल्लेख नहीं होता है यदि इन पसनों पर गौर किया जावे तो कई चरसुओं पर तो इसके निर्माण की रीति तक नहीं लिखी रहती और कई जगह एक्सपायरी डेट का समान छिक्ते हुए भी देखा जाता है? इन उत्पादों को शहर की गलियों सहित गांव गांव में बेचा जा रहा है और शहर सहित आसपास के कस्बों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में लाखों का कारोबार होता है।

सरकारी बैकों में दलालों का राज, ग्रामीणों का नही होता बगैर पैसों का काज

हरिभूमि न्यूज़/साईंखेड़ा। प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण कस्बे में निवास करने वाले किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना आदि शामिल हैं, किसानों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैकों की शाखाएं खोली गई हैं। मगर अक्सर देखा जाता है कि इन बैकों में बैठे अधिकारियों की मनमानी के चलते किसानों को शासन की योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका उदाहरण इस समय शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक में देखा जा रहा है। जहां पर क्षेत्र के किसानों द्वारा आरोप लगाते हुए बताया है कि इन बैकों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के किसान बैंक के चक्कर लगाते पर मजबूर हो रहे हैं? क्षेत्र के कुछ किसानों ने हमारी हरिभूमि टीम से चर्चा करते हुए बताया कि किसान अपने कार्यों के लिए परेशान होते देखे जा रहे हैं? जिसमे क्षेत्र के कुछ ग्रामीण किसान जो कि खेती किसानों कर अपनी जीविका चलाते आ रहे हैं, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए गांव से चलकर शहर पहुंचता है तो अधिकारियों द्वारा उसे कार्ड बनवाने के लिए सीधे दलालों के पास जाने की सलाह दे देते हैं? जब वह उनके पास पहुंचता है तो सीधे 10 से लेकर 20 प्रतिशत राशि की बात पर ही कार्ड बनाने का काम कही जाती है, इस स्थिति में जब किसान अधिकारियों से चर्चा करते है तो बैकों अधिकारियों द्वारा उस किसान को महिनो तक घुमा घुमाकर परेशान कर दिया जाता है।

पशुओं के कूरूरता पूर्वक परिवहन पर अंकुश लगाने में प्रशासन हो रहा है फैल..

हरिभूमि न्यूज़/साईंखेड़ा। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आस पास के कस्बा क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक मवेशी बाजारों के माध्यम से खुलेआम पशुओं की तस्करी होने की चर्चा आम होती जा रही है। क्षेत्र में लगने वाले इस मवेशी बाजार में सैकड़ों की संख्या में पशु बिक्री के लिये आते जो कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से बैल जो कृषि योग्य नहीं होते व गायो जो दूध देना बंद कर देती हैं उन्हें कुछ दलालनुमा व्यक्ति ऐसे पशुओं को दलाल कसाईयों को दोगुनी कीमत के माध्यम से पशु मालिकों से खरीदाते देते हैं और पशु मालिक भी थोड़े से पैसों के लालच में जिन्दगी भर धी धी देने वाली गायों व गर्भों धूव व बरपात के मौसम में मेहनत कर कमाई खिलाने वाले बैलों को इन कसाईयों के हवाले कर देते हैं। जनचर्चाओं में तो यह तक बताया जाता है कि बाजार के दिन बाहर से आने वाले इन कसाईयों के कुछ दलाल गांव गांव घूमकर इस प्रकार के बूढ़े पशुओं की खोज करते हुये पशु मालिकों को उन्हे बेचने के लिये उकसाते हुये देखा जा सकता हैं।

रेल पुलिस की उदासीनता के चलते यात्रियों को परेशानी झेलने के लिये होना पड़ रहा है मजबूर , वाहन मालिकों की मनमानी से प्लेट फार्म पर प्रवेश करना हो रहा मुश्किल



हरिभूमि न्यूज़/गाडरवारा।

जहां एक ओर रेल विभाग द्वारा अपने यात्रियों के लिये अच्छी सुविधायक प्रदान करने के लिये नई नई व्यवस्थायें बनाते हुये देखा जा रहा है। मगर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस सहित रेल सुरक्षा फोर्स की उदासीनता के चलते रेल यात्रियों को जिस प्रकार से परेशानियों का सामना करते हुये देखा जा रहा है। सच्चाई यह उजागर करने से नहीं चूक रहा है कि मानों रेल पुलिस द्वारा मनमानी करने वालों को अपनी ओर से पूर्णरूप से छूट प्रदान कर दी गई..? क्योंकि नगर के रेलवे स्टेशन की सच्चाई को मीडिया द्वारा प्रमुखता के साथ उजागर किये जाने के बाद भी रेल पुलिस से लेकर रेल सुरक्षा फोर्स की चुप्पी निश्चित उनकी कार्यशैली पर सबाल खड़े करने से नहीं चूक रही है..? नगर के रेल्वे स्टेशन का जो नजारा देखने मिल रहा है उससे यह प्रतीत होने से नहीं चूक रहा है कि मानों रेल प्रशासन द्वारा आर्टों सहित अन्य वाहन मालिकों को अपने वाहन रेलवे स्टेशन परिसर में खड़े करने की पूर्णरूप से छूट प्रदान की दी गई जिसके चलते उनके हौसले बुलंद नजर आने से नहीं चूक रहे है। इसी का परिणाम है कि रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है। क्योंकि रेल यात्रियों की सुरक्षा से लेकर रेलवे प्लेट फार्म व परिसर की संपूर्ण ज़म्मेदारी रेल सुरक्षा फोर्स सहित रेल पुलिस की होती है। मगर स्थानीय रेलवे स्टेशन के हाल तो यह बने हुये है कि मानों आरपीएफ व जीआरपी पुलिस को कोई लेना देना ही नहीं है..? इसी का परिणाम है कि जहां आर्टों चालक अपनी सवारियों बैठने के लिये रेलवे प्लेट फार्म के मुख्य द्वार पर अपने आर्टों खड़े करते हुये यात्रियों का ईंतजार करने से नहीं चूकते है। वहीं दूसरी ओर रेल्वे स्टेशन के लिये अपने किसी रिस्तेदार या फिर सगे संबंधी को लेने के लिये पहुंचने वाले लोगों द्वारा भी अपने वाहनों को मुख्य द्वार के

ठीक सामने खड़े कर दिये जाते है। इस स्थिति में जब रेल यात्री प्लेट फार्म से नीचे आते है तो उन्हे परेशानियों का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखा जाता है। इसमें सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को झेलने पड़ती है जब कोई रेल यात्री यात्रा करने के लिये स्टेशन पहुंचता है और उसकी ट्रेन प्लेट फार्म पर खड़ी होने के साथ साथ छूटने की स्थिति में रहती है तो इस तरह स्टेशन के मुख्य द्वारा पर अघोषित रूप से बना हुआ वाहन स्टेशन के चलते लोग अपने ट्रेन पकड़ने से चूकते हुये आसानी से देखे जा सकते है। इसमें महिला यात्रियों की स्थिति गंभीर हो जाती है। क्योंकि मुख्य द्वार पर खड़े होने वाले वाहनों के चलते महिलाओं का प्लेट फार्म पर पहुंचने से लेकर नीचे आना भी मुश्किलों से खाली नहीं रहता है। हद तो तब हो जाती है जहां रेल्वे प्लेट फार्म के पास अपने वाहनों के साथ मनचले खड़े हुये ट्रेन से आने जाने वाली महिलाओं के साथ छिटाकशी करने से नहीं चूकते है। इतना ही प्लेट फार्म के सामने पड़े हुये रेलवे की खाली जगह पर अनेक तत्वों द्वारा नियम विरुद्ध जिस तरह से अपने चाय, पान सहित अन्य प्रकार की सामग्री विक्रय करने वालों द्वारा हाथ ठेले स्थापित किये गये है उन पर दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहने के चलते वह महिला यात्रियों को आते जाते समय छिटाकशी करते हुये देखे जाते है। इस तरह नगर के रेल्वे स्टेशन की लगातार बिगड़ रही व्यवस्थाओं के चलते रेल यात्रियों को जहां दहशत में देखा जा रहा है तो दूसरी ओर रेल प्रशासन के साथ साथ आरपीएफ व जीआरपी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सबाल खड़े होने से नहीं चूक रहे हैं...? बताया जाता है कि रेलवे की भूमि पर बगैर अधिकारियों की सहमति के बगैर कोई भी अपना टप या फिर फ़रसी भी जीच को स्थापित नहीं कर सकता है। मगर इसके बाद भी देखा जा रहा है कि रेलवे प्लेट फार्म के सामने वाहन स्टेन्ड की ओर जाने वाले मार्ग पर जहां खुलेआम पान सहित अन्य सामग्री

के टप स्थापित होते चले जाने के कारण रेल प्रशासन की भूमिका संरक्षण की मुद्रा में नजर आने से नहीं चूक रही है..? वहीं दूसरी ओर वाहन मालिको द्वारा जिस तरह से प्लैट फार्म के मुख्य द्वार को अघोषित रूप से वाहन स्टेन्ड का रूप दे डाला है वह यात्रियों के लिये परेशानी का कारण बनने से नहीं चूक रहा है। कहने के लिये तो यहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। मगर उसका पालन रेल सुरक्षा फोर्स व जीआरपी की उदासीनता के चलते पालन होते हुये दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं रेल्वे स्टेशन से आगे की ओर मुख्य मार्ग के नजारे को देखकर तो यह लगता है कि मानों नगर पुलिस द्वारा आर्टों चालको को मुख्य मार्ग पर अपने आर्टों खड़े करने के लिये पूरी छूट दे रखी है जिसके चलते कई घंटों तक दुकानों के सामने मुख्य मार्ग पर आर्टों चालको का साम्राज्य स्थापित हो जाता है जिसके चलते अन्य वाहनों का निकलना भगवान भरोसे रहते हुये देखा जा रहा है। इस प्रकार से नगर के रेल्वे स्टेशन से आर्टों चालकों की मनमानी के जिस प्रकार से नजारे देखने मिल रहे है इस सच्चाई को मीडिया द्वारा समय समय पर प्रमुखता के साथ उजागर किया जाता रहा है। मगर इसके बाद भी रेल पुलिस से लेकर रेल सुरक्षा फोर्स द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं फ़क़वे जाने का परिणाम है कि इस तरह मनमानी करने वालों के हौसले जहां सातवे आसमान पर नजर आते हुये जान पड़ रहे है और रेल यात्रियों की अपनी जिन्दगी दाव पर लगाते हुये यात्रा करने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है..? वहीं दूसरी ओर नगर में चलने वाले आर्टों चालकों द्वारा जिस प्रकार से अपनी मनमानी पर उतारू होते हुये आर्टों चलाये जा रहे उसके चलते स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि नगर की सड़को पर आर्टों चालकों द्वारा चलते मुख्य मार्गों पर ही अचानक बीच रास्ते पर ही अचानक आर्टों रोकने से नहीं चूकते है। इस स्थिति में जब उनके पीछे कोई दो पाहिया वाहन चालक या फिर अन्य कोई

वाहन चल रहा होता है तो अचानक आर्टों को रोके जाने के कारण आर्टों से टकराने से नहीं चूकता है और यही हाल आर्टों मोड़ने के समय देखा जाता है जो चलते चलते अचानक अपने आर्टों को मोड़ने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं घटित होना आम बात हो चुकी है। कुछ इसी तरह का हाल रात के समय देखने मिलता है। क्योंकि आर्टों चालको द्वारा अपने आर्टों के ऊपरी भाग पर लगाये गये सफेद एलईडी लाईन सामने से आने वाले वाहन चालक को परेशानी में डालते हुये दुर्घटना का प्रमुख कारण बनने से नहीं चूक रहे है। वहीं दूसरी ओर नगर के रेल्वे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर लगी हुई चाय नास्ता दुकानों के सामने यह आर्टों चालक मुख्य मार्ग पर घंटो तक अपने आर्टों को खड़ा करते हुये चाय नास्ता करने में मग्न हो जाते है जिसके चलते स्टेशन की ओर आने जाने वाले रेलयात्रियों के साथ साथ आम लोगों को परेशानियों का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है। इस तरह स्टेशन क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर घंटों तक खड़े रहने वाले इन आर्टों से सबसे अधिक परेशानी व खतरा उन लोगों को पैदा हो रहा है जो अपनी बाइक के माध्यम से शीघ्रता के साथ किसी ट्रेन को पकड़ने जा रहे होते है। बताया जता है कि यह आर्टों चालक ट्रेन से उतरने वाली सवारियों को बैठाने के बाद मुख्य मार्ग किनारे लगी हुई चाय पान दुकानों के सामने जिस तरह आर्टों खड़े करते हुये अन्य दूसरी सवारियों के ईंतजार में घंटो तक जागे की स्थिति बनाने से नहीं चूकते है। इस हालत इस मार्ग से अन्य वाहन चालको का निलना मुश्किल हो जाता है। जिसमें मुख्य रूप से देखा जावे तो बाइक चालकों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखे जाते है। सबसे अधिक परेशानी तो उन लोगों को होती है जो किसी ट्रेन का समय होने के दौरान ट्रेन को पकड़ना होता है तो वह इन आर्टों की भीड़ में फसकर अपनी ट्रेन चलने से नहीं बच पाता है।

ग्राम घुटंगो गांव के अंदर सड़कों पर बह रहा नालियों का पानी, स्वच्छता अभियान सहित विकास कार्यों की खुल रही पोल..



हरिभूमि न्यूज़/गाडरवारा।

जहां सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर करोड़ों रूपया खर्च करते हुये गांवों की सूरत बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रहा है। मगर इसके बाद भी यदि गांव के सड़को पर नालियों का गंदा पानी बहते हुये नजर आने से पंचायत के विकास कार्यों के साथ साथ स्वच्छता के नाम पर खर्च की जाने वाली राशि की सच्चाई पंचायत की भूमिका पर सबाल खड़े करते हुये जांच की ओर संकेत देने से नहीं चूक पाती है..? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय चल रहे ज्येष्ठ माह के दौरान

जनपद पंचायत साईंखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बनेखड़ी छोटी के ग्राम घुटंगों में देखने मिल रहा है। बताया जाता है फ़्क चल रहे ज्येष्ठ मास के दौरान यहां गांव के अंदर सड़को पर सावन भादों माह के नजारे फ़दखाई देने से नहीं चूक रहा है। क्योंकि ग्राम विकास के नाम पर हर साल लाखों रूपया खर्च होने के बाद भी गांव के अंदर की सच्चाई इस तरह से बनी हुई है कि नालियों का गंदा पानी सड़को पर बहने के साथ साथ लोगों के घरों में प्रवेश करने से नहीं चूक रहा है। इस सच्चाई के चलते पंचायत के विकास कार्यों की सच्चाई पर सबाल खड़े होने के साथ साथ

सरकार के स्वच्छता अभियान पर भी ग्रहण लगने से नहीं चूक रहा है। इस संबंध में ग्रामवासियों का कहना है कि गांव के अंदर सड़को का हाल इस तरह बना हुआ है कि सड़को पर फैल रही गंदगी के चलते जहां बच्चों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है तो दूसरी ओर चल रहे गर्मी मौसम के बीच गंदे पानी के कारण अनेक प्रकार के मच्छर जन्म ले रहे है। हाल यह बना हुआ है फ़्क नालियों का सड़को पर फैले हुये गंदे पानी के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे है। इस स्थिति के चलते गांव में भयानक बीमारी फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा

सकता है। इस तरह ग्राम घुटंगों में फैल रही गंदी को लेकर बीते हुये दिवस ग्रामवासियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को एक आवेदन देते हुये उचित कार्यवाही की मांग की गई है। इस संबंध में ग्रामवासियों का कहना है कि वह पंचायत के जन प्रतिनिधियों से इस समस्या के ल्दान को लेकर अनेको बार गुहार लगा चुके है। मगर पंचायत द्वारा ग्रामवासियों की समस्या को जिस तरह से नजर अंदज किया जा रहा है उसके चलते लोग परेशान होने के साथ साथ व्ष्व गुरू बनने की ओर अग्रसर हो रहे देश में आज की नरकीय जिंदगी जीने के लिये मजबूर होते हुये देखे जा रहे है।

कलेक्टर ने किया गाडरवारा- बारहाबड़ा नवनिर्मित सड़क मार्ग का निरीक्षण



हरिभूमि न्यूज़/गाडरवारा।

क्षेत्र के भ्रमण पर निकली हुई ज़ला कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने बीते हुये शुक्रवार को 2639.60 लाख रुपये की लागत से 17.20 किलोमीटर लम्बाई की गाडरवारा से बारहाबड़ा तक नवनिर्मित सड़का की निरीक्षण



निरीक्षण करते हुये उन्होंने निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने भवन निर्माण से जुड़े शेष कार्यों सड़क एवं रिटैनिंग वॉल के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-

सीमा में दो माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सुश्री प्रियंका नेताम सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

निजी शालाओं में सुविधाओं की कमी, शिक्षित बेरोजगारों का घडल्ले से हो रहा शोषण फिर भी प्रशासन मौन



निजी शालाओं के आकर्षण में पड़कर बच्चों का दाखिला करवा देते हैं और बाद में पछाते हैं। इस समय शहरों के आलाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जावे तो ऐसी अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर मात्र 10 वीं से 12 वीं पास युवक युवती आलव वेतन मानदेय पर शिक्षक के रूप में

सेवाये देकर बेरोजगारी के समय में शोषित हो रहे हैं। इन निजी शालाओं में ना तो छात्र-छात्राओं को पीने के लिये शुद्ध पेयजल, पेशाबघर, शौचालय, खेल मैदान व बैठने के लिये हवादार कमरे भी नहीं हैं। शहर के साथ साथ गांवों में ऐसी कई शालायों तो किराये के रहवासी मकानों में लग रहीं हैं इसके बाद भी शिक्षक संस्थाओं के संचालक पालकों से सभी व्यवस्थाओं के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। वहीं कुछ स्कूलों के संचालको बात करते तो वह गांव में इस प्रकार से अगेजी स्कूलों का संचालन कर रहे है, जिन्हे खुदे तो अगेजी आती नहीं है और वह बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों का संचालन करने बैठे हुए है। अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि क्या इन स्कूलों में बच्चों द्वारा दी जाने वाली फीस के मुताबिक पढ़ाई हो पायेगी? पालकों को यहिये कि वे शिक्षण सत्र दौरान ही अपनी जागरूकता का परिचय देते हुये पूर्ण नियम कानून से चलने वाली शालाओं में ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाये जिससे उनका भविष्य सेंवर सके तथा शिक्षा विभाग से अपेक्षा की जाती है

कि गाजर घास की तरह गांव गांव उग्न शिक्षण संस्थाओं की जाँच करे जो नियमों को दर किनार करके जेबें भरने में लगे हुई हैं। विदित हो कि शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को खेलने के लिये निश्चत भूखंड का मैदान होना जरूरी है किंतु यहाँ जो देखने में आ रहा है उससे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि शिक्षण संस्थाओं के नाम पर मात्र पैसा कमाया जा रहा है, किराये के मकानों में संचालित होने वाली अगेजी माध्यम की एक संस्था का तो यह है हाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों वाहन सुविधा के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, और उसी वाहन में खुलेआम दिन भर सवाली द्रोई जा रह है। यह सच्चाई गांव गांव संचालित होने वाली शिक्षण संस्थाओं में चल रहे वाहनों में आसानी से देखा जा सकता है कि जिनके पास न तो बच्चों को लाने ले जाने का परमिट है और न ही वाहनों के जरूरी कागज उसके बाद भी खुलेआम बच्चों को सवारियों के साथ भेड बकरी की तरह भरने से नहीं चूक रहे है?



खबर संक्षेप

समाजसेवा, रक्तदान, एवं मानवता की सेवा हेतु पुष्पेंद्र नामदेव को राज्यपाल ने किया सम्मानित

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की मध्य प्रदेश राज्य शाखा, भोपाल द्वारा विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य पाल मंगु भाई पटेल रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम अनूपपुर से हर्मुनिटी केनर फेमिली वेलफेयर एंड हेल्थ सोसायटी के संचालक पुष्पेंद्र नामदेव को मानव सेवा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुष्पेंद्र कुमार नामदेव द्वारा लंबे समय से मानवता की सेवा, समाज सेवा, जस्ूरतर्मद लोगों की सहायता तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों की सराहना की। संस्था गरीब बेसहारे, लोगों की सेवा के साथ साथ समय मानव सेवा से जुड़े विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निमाती रही है। इस सम्मान पर पुष्पेंद्र नामदेव ने कहा ने कि यह सम्मान पूरी टीम और समाज के सहयोग का परिणाम है।

मैया अभियान बना जनभागीदारी का प्रेरक अभियान , नर्मदा घाटों पर जारी स्वच्छता संदेश



डिंडोरी।

जिला मुख्यालय में पिछले करीब छह माह से लगातार संचालित हो रहा “मैया अभियान” अब केवल स्वच्छता कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जनभागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। नर्मदा तट स्थित घाटों पर आयोजित इस अभियान में जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और

आम नागरिक एकजुट होकर श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर घाटों की साफ-सफाई करते हैं। साथ ही समाज में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से लोगों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की भावना मजबूत

हो रही है।कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया स्वयं अभियान में शामिल होकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ श्रमदान करती नजर आती हैं। नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी नियमित रूप से अभियान में सहभागिता निभा रहे हैं। कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया द्वारा लगातार लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और “स्वच्छ डिंडोरी, सुंदर डिंडोरी” का

संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की जा रही है। अभियान के प्रभाव से जिले में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है और आमजन भी बढ़-चढ़कर इसमें भागीदारी कर रहे हैं।सफाई अभियान के दौरान कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदोरिया, एसडीएम रामबाबू देवगंज, नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

फिटनेस के प्रति जागरूक हुए बच्चे और नागरिक



डिंडौरी।

कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित “आरोह-2026” ग्रीष्मकालीन शिविर के तहत रविवार को मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन किया गया। 5 मई से 5 जून तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों, खिलाड़ियों, अभिभावकों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।कार्यक्रम के दौरान एरोबिक्स, योग एवं सामूहिक फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों के साथ उनके परिजन और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा



लिया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन, सामुदायिक सहभागिता तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर एसडीएम रामबाबू देवांगन सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयं फिटनेस गतिविधियों में शामिल होकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में “स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज” का संदेश भी दिया गया।आयोजन को सफल बनाने में नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी मोहम्मद अहमद खान, चेताराम अहिरवार, आरती सोंधिया, सुनीता, लक्ष्मी बनावल, राजकुमार एवं आनुष



अधिकारी डॉ. समीक्षा सहित नगर पालिका स्टाफ और खेल प्रमियों का विशेष सहयोग रहा। एरोबिक्स प्रशिक्षण आदर्श परस्ते एवं प्रशिक्षकों की टीम द्वारा कराया गया।कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने आयोजन की सराहना करते हुए प्रत्येक रविवार इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि जिलेवासियों को खेल और फिटनेस के माध्यम से

स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जा सके।खेल विभाग के अनुसार “आरोह-2026” के अंतर्गत आगामी दिनों में भी खेल, योग, फिटनेस और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन जारी रहेगा। इसी क्रम में आगामी 18 मई 2026 को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा तट पर विशेष योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों से सहभागिता की अपील की गई है।

नेशनल लोक अदालत का हुआ सफल आयोजन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

मओप्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर श्रीमती माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में 09 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय कोतमा/राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय अनूपपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल के द्वारा, मां सरस्वती जी के चित्र में पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मनोज कुमार लद्विया, प्रथम जिला न्यायाधीश/संयोजक नेशनल लोक अदालत नरेन्द्र पटेल, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती चौनवती ताराम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रावेन्द्र कुमार सोनी, सुश्री सुधा पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाँबी सोनकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री सृष्टि साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट, अर्पण चौधरी प्रिषुषु जज, जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल, जिला अधिवक्ता बार संघ से अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार, सचिव राम कुमार राठौर, शासकीय अभिभाषक पुणेन्द्र कुमार मिश्रा, लीयल एड डिफेंस काउंसेल संतदास नापित, जिला अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्तागण खण्डपीठ के सुलहकर्ता सदस्यगण, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, पुलिस बल, बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग, जिला न्यायालय एवं जिला प्राधिकरण अनुपूर के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से

अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक 115, चैक बाउंस 30, वैवाहिक प्रकरण 11, विद्युत प्रकरण 65, अन्य प्रकरण 430 एवं प्रीलिटिगेसन प्रकरण 178, इस प्रकार कुल 899 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें कुल राशि 1,40,05,122 (एक करोड़ चालीस लाख पांच हजार एक सौ बाईस रूपयें) की राशि अवाई की गई। अनूपपुर जिले की नेशनल लोक अदालत में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने त्वरित न्याय और आपसी समझौते की नई मिसाल पेश की।विद्युत प्रकरण से जुड़े मामले में जहां पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट के तहत जिला जेल भेजा गया था, वहीं शनिवार को तीसरे आरोपी ने स्वयं न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया और राजीनामे के माध्यम से पूरे मामले का समाधान हो गया। जानकारी के अनुसार, 02 मई 2026 को न्यायाधी सुश्री सुधा पाण्डेय के न्यायालय द्वारा विद्युत प्रकरण में आरोपी मनोज कुमार राठौर एवं दीपक गुप्ता को गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जिला जेल अनूपपुर भेजा गया था। इसके बाद नेशनल लोक अदालत में मामले ने सकारात्मक मोड़ लिया, जब प्रकरण के अन्य आरोपी एहसान अली पिता वाजिद अली, उम्र 60 वर्ष, निवासी अनूपपुर ने स्वयं 09 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक-03 के विशेष प्रकरण क्रमांक 144/2026 में 31,069 रुपये की राशि जमा कर आपसी राजीनामे के आधार पर विवाद का निराकरण किया गया। इस पहल को न्यायालय परिसर में एक प्रेरणादायी सफलता की कहानी के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि त्वरित न्याय के साथ समाज में सौहार्द और समझौते की भावना को बढ़ावा देना भी है।

सरपंच की मेहनत लाई रंग बुढ़नेर नदी पर 13 करोड़ से अधिक लागत से बनेगा पुल

डिंडौरी।

जिले के अमरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कमको मोहनिया के पोषक गांव दिवारी और मवाई जनपद पंचायत के ग्राम परसा टोला के बीच बहने वाली बुढ़नेर नदी पर लंबे समय से प्रस्तावित बड़े पुल निर्माण की मांग अब तेजी पकड़ने लगी है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सरपंच संघ जिला डिंडौरी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर फूल सिंह मरकाम द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari को भेजे गए मांग पत्र के बाद केंद्रीय मंत्रालय सक्रिय हो गया है। मंत्रालय ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश को सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं जिससे क्षेत्रवासियों में पुल निर्माण को लेकर नई उम्मीद जगी है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र कार्यालय नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा सीआरआईएफ योजना के तहत सड़क एवं पुल विकास कार्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमको मोहोदिया



दिवारी परसटोला मार्ग पर बुढ़नेर नदी में पहुंच मार्ग सहित लगभग 150 मीटर लंबे पुल का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा तैयार प्रस्ताव में पुल निर्माण की अनुमानित लागत 7 करोड़ 50 लाख रुपये बताई गई है जबकि दोनों ओर लगभग 2670 मीटर पहुंच मार्ग निर्माण पर 2 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च प्रस्तावित हैं। जीएसटी मूल्य वृद्धि और भूमि अर्जन सहित कुल परियोजना

लागत लगभग 13 करोड़ 06 लाख 76 हजार रुपये आंकी गई है।पत्र में उल्लेख किया गया है कि बरसात के दिनों में बुढ़नेर नदी उफान पर होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई गांवों का संपर्क टूट जाता है और लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। छात्रों और ग्रामीणों को स्कूल कॉलेज और बाजार पहुंचने के लिए 40 से 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है जिससे

समय और आर्थिक नुकसान दोनों होता है।सरपंच संघ अध्यक्ष इंजीनियर फूल सिंह मरकाम ने बताया कि पुल निर्माण की मांग वर्षों पुरानी है और आजादी से पहले से क्षेत्र के लोग इसकी आवश्यकता महसूस करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बुढ़नेर नदी पर पुल बनने से डिंडौरी और मंडला जिले के कई गांवों का सीधा संपर्क स्थापित होगा जिससे शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार और आवागमन की सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा।

रामपुर-बटुरा खदान से उठी हुंकार किसानों ने छेड़ी निर्णायक लड़ाई

रामपुर-बटुरा खुली खदान परियोजना से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने एक बार फिर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। ग्राम पंचायत खांडा में आयोजित बैठक में क्षेत्रभर के 12 पंचायतों के प्रतिनिधियों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर शोषण, अवैध उत्खनन, विस्थापन, बेरोजगारी और वन्य जीवों के आतंक के खिलाफ सामूहिक आंदोलन का संकल्प लिया। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने साफ कहा कि अब चुप्पी नहीं, बल्कि सड़क से लेकर शासन तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

एसईसीएल प्रभावित क्षेत्र में वर्षों से जमा आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। खदान परियोजनाओं, निजी कंपनियों और प्रशासनिक उदासीनता से परेशान ग्रामीणों ने

ग्राम पंचायत खांडा में आयोजित बैठक में खुलकर अपनी पीड़ा रखी। बैठक में केवल रामपुर-बटुरा खुली खदान परियोजना ही नहीं, बल्कि अवैध उत्खनन, हाथी-भालू के हमलों से हो रही मौतें, सिंचाई संकट, पेयजल की समस्या, स्थानीय बेरोजगारी और आदिवासियों के अधिकारों के हनन जैसे मुद्दों पर तीखी चर्चा हुई। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जल, जंगल और जमीन को लगातार लूटा जा रहा है। कई कंपनियां यहां की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। बाहर से आए लोग रोजगार पा रहे हैं जबकि स्थानीय युवा पलायन को मजबूर हैं। बैठक में तय हुआ कि अब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और संघर्ष को जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा।

शांत बैठे रहे तो सब शांत हो गया-भूपेश शर्मा

बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश शर्मा ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र के लोग चुप बैठे रहे, जिसका फायदा कंपनियों और जिम्मेदार अधिकारियों ने उठाया। उन्होंने कहा कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। खदानों से धूल और

प्रदूषण बढ़ रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं और किसान अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र रूप लेगा।

अवैध उत्खनन और कोयला घोटाले पर भी उठी आवाज

बैठक में सबसे गंभीर आरोप रामपुर खुली खदान परियोजना से निकलने वाले कोयले को लेकर लगाए गए। वक्ताओं ने दावा किया कि क्षेत्र से निकलने वाला उच्च गुणवत्ता का कोयला “दो नंबर” के खेल में बाहर भेजा जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर भारत सरकार को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे खेल में मौन हैं। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध उत्खनन और कोयला परिवहन की निगरानी अब जनता खुद करेगी।

वन्य जीवों का आतंक, किसान दहशत में

बैठक में हाथी और भालू के लगातार बढ़ते हमलों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ग्रामीणों ने कहा कि खदानों और जंगल कटाई के कारण वन्य जीव गांवों की ओर आ रहे हैं, जिससे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। कई परिवार उजड़

चुके हैं लेकिन प्रशासन केवल मुआवजे की औपचारिकता निभा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। बैठक में वन्य जीव प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत और सुरक्षा योजना की मांग की गई।

स्थानीय युवा बेरोजगार, बाहरी लोगों का कब्जा

ग्रामीणों ने कंपनियों पर आरोप लगाया कि क्षेत्र की जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल तो यहां हो रहा है, लेकिन रोजगार बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। स्थानीय शिक्षित और अशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि कंपनियां ष्क और रोजगार के बड़े-बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों को केवल आश्वासन मिलता है। अब रोजगार में स्थानीयों को प्राथमिकता दिलाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा।

17 मई को बाकी में होगी निर्णायक महापंचायत

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 17 मई को बाकी

में एक विशाल जनसभा और महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक पंचायत या एक कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे संभाग में हो रहे शोषण, दमन और अन्याय के खिलाफ है। गांव-गांव में जनजागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। वक्ताओं ने प्रशासन और प्रबंधन को चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जनआंदोलन खड़ा होगा।

बैठक में रहे प्रमुख लोग उपस्थित

बैठक में पूर्व एसडीएम एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शांति मनमोहन चौधरी, वन समिति सभापति चंद्रकुमार तिवारी, सांसद प्रतिनिधि राजकमल मिश्रा, किसान नेता आदित्य त्रिपाठी, ओमप्रकाश द्विवेदी पत्रकार, सरपंच-उपसरपंच सहित 12 पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा अखिलेश त्रिपाठी, संदीप द्विवेदी, त्रिवेणी राव, अमित शर्मा, नीलू राव, शिवप्रसाद चौधरी समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर संघर्ष का संकल्प दोहराया।



अमरपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन अजय सिंह का हुआ भव्य स्वागत

अमरपुर। विकासखंड मुख्यालय अमरपुर में अजय सिंह के आगमन ने पूरे क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गरमा दिया। ब्लाक कांग्रेस कमेटी अमरपुर द्वारा उनके स्वागत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें शहपुरा विधानसभा सहित जिलेभर से कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार को आयोजित अति आवश्यक बैठक में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। जगह-जगह फूल-मालाओं, नारों और ढोल-नगाड़ों के साथ “राहुल भैया” का आत्मीय अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से कांग्रेस समर्थकों ने घेरा। आयोजित बैठक का नेतृत्व डिंडोरी विधायक व जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह मरकाम द्वारा किया गया। इस दौरान अजय सिंह ने संगठनात्मक गतिविधियों की गहन समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। इसके साथ ही श्री सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नवी जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उनके संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरा परिसर कांग्रेस के नारों से गूंज उठा।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमरपुर के पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति और उत्साह ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। अमरपुर में लंबे समय बाद कांग्रेस का ऐसा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, शहपुरा पूर्व विधायक व कांग्रेस महासचिव भूपेंद्र मरावी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमरपुर अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमन पाठक, जिलाध्यक्ष सरपंच संघ फूल सिंह मरकाम, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमंत हरदहा, समस्या निवारक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष तोक सिंह मरावी, ब्लॉक उपाध्यक्ष शकील अहमद, कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग विधानसभा अध्यक्ष देव सिंह भारती, ब्लॉक संगठन मंत्री शाहिद तुर्क, अमरपुर मंडलम अध्यक्ष संदीप शाह परस्ते, आदिवासी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष केवल कृष्ण नेटी, समाज कल्याण प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव लियाकत अली, बैगा समाज ब्लॉक अध्यक्ष चमर सिंह चड़्चढ़िया, आदिवासी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजेश पाटले, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री राम सिंह मरावी, मंडलम उपाध्यक्ष मनीष गायकवाड़, शान मंसूरी, उपसरपंच बोधघुण्डी, शंकर सिंह कुशराम, परसेल मंडलम अध्यक्ष गणेश पुषाम, महेंद्र वास्पे, मनोज ताराम, बलराम राजपूत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

